श्री मनीराम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी और लोकदल के दो मेम्बर पार्लियामेंटरी आफिस, एनेक्सी में से आ रहे थे, मगर पुलिस ने उनको नहीं आने दिया और कहा कि प्राइम मिनिस्टर का लंच है, इस लिए इधर से नहीं जा सकते। वे लोक सभा को आ रहे थे। लोक सभा के मेम्बर को लोक सभा को आते हुए रोकना बुरी बात है, गलत बात है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Mani Ram Bagri, I will look into it. I said I will look into it. Now, Mr. Venkataraman to make a statement.

14.33 hrs.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (KERALA), 1981-82

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN): I beg to present a statement (Hindi and English version) showing Supplementary Demands for Grants in respect of the State of Kerala for 1981-82.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): Earlier it was Assam. Now it is Kerala! (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now matters under Rule 377.

14.35 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) RAJADHYAKSH COMMITTEE RECOMMENDATIONS ON STATE ELECTRICITY BOARDS WITH PARTICULAR REFERENCE TO INADEQUATE POWER SUPPLY IN MAHARASHTRA.

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में उद्योगों एवम् किसानों को बिजली कम मात्रा में दी जा रही है, जिससे औद्योगिक उत्पादन तथा खेती पर असर पड़ रहा है। पम्प के माध्यम से खेतों की सिंचाई की जाती है, लेकिन राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली सिर्फ चार पांच घण्टे के लिए दी जाती है, जिससे कृषक पूर्ण रूप से फ़सल प्राप्त करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, उनकी पैदावार कम होती है। इस तरह उनका आर्थिक बोझ भी अधिक बढ़ जाता है और पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

मेरे ही जिले मेलघाट में, जो कि एक आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र है, तथा आस-पास के इलाकों में बिजली के खंबे तो सरकार ने लगा दिए हैं, लेकिन बिजली न होने की वजह से वहां अंधकार ही रहता है। इसी प्रकार जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, महाराष्ट्र में वहां भी स्वतन्त्रता के बाद बिजली की सुविधाएं तो दे दी हैं, लेकिन बिजली ठीक प्रकार से पहुंचती नहीं है।

आदिवासियों तथा अल्प भू-धारकों को शासन की तरफ़ से पम्प वगैरह लगाने के लिए सबसिडी तो दी गई है, लेकिन अगर विद्युत प्राप्त न हो, तो सिंचाई का कार्य वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है। भारत एक कृषि-प्रधान देश है और यहां के अधिकतर लोग खेती पर निर्भर करते हैं। उनका जीवन-स्तर तभी सुधर सकता है, जब कि उन्हें बिजली वगैरह की सुविधाएं प्राप्त होती रहें और वे अपनी खेती से पूरी फ़सल प्राप्त कर सकें।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह राज्य बिजली बोर्डों के काम-काज के बारे में राजाध्यक्ष समिति की सिफ़ारिशों पर तत्काल कार्रवाई करे, ताकि इनके काम-काज में सुधार हो सके। बिजली के उत्पादन और वितरण में केन्द्र सरकार को अधिकाधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे कृषि और औद्योगिक विकास को गति मिल सके।